

Daily Current Affairs

Date : 31 January, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	केन्द्रीय आर्थिक सर्वेक्षण - 2025-26 में राजस्थान की राजस्व स्थिति
2.	47वाँ मरु महोत्सव 2026 - जैसलमेर
3.	नेशनल मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन - जयपुर
4.	राजस्थान में अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT)
5.	रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) : चित्तौड़गढ़
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. रणथम्भौर नेशनल पार्क में मोबाईल फोन के उपयोग पर रोक 2. 7वीं ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3. क्रिकेट अंपायर रघुवीर सिंह राठौड़ का निधन 4. 'ऑपरेशन नॉकआउट' 5. चतुर्थ कुलगुरु चल वैजयन्ती खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता 6. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) 7. छांपाला भैरू जी महाराज का लक्खी मेला 8. राजस्थान की झाँकी को पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड
7.	बम चक्रवात (Bomb Cyclone)
8.	PAIMANA
9.	आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की मुख्य बातें
10.	आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: भारत एक 'उद्यमशील राज्य'
11.	विश्व परमाणु परिदृश्य रिपोर्ट

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



केन्द्रीय आर्थिक सर्वेक्षण - 2025-26 में राजस्थान की राजस्व स्थिति



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जारी, केन्द्रीय आर्थिक सर्वेक्षण - 2025-26 में राजस्थान के राजस्व घाटे में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो राज्य के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेज तथा प्रशासनिक सुधारों को रेखांकित करती है।



मुख्य बिन्दु:

- राजस्व घाटा** : वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश का राजस्व घाटा ₹38,954 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों में घट कर ₹31,939 करोड़ रह गया।
- आंकलन** : वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के आय व्ययक अनुमान में राजस्थान के राजस्व घाटे के ₹31 हजार 9 करोड़ रहने की संभावना व्यक्त की गई थी।
- मुद्रा स्फीति** : आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान में मुद्रा स्फीति 6.39 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 4.34 प्रतिशत पर आ गई।
- वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान राजस्थान में खुदरा मुद्रा स्फीति 0.81 प्रतिशत रही है, जो प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन, लक्षित हस्तक्षेप और प्रशासनिक समन्वय को दर्शाती है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

प्रकार	राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
दायरा	इसमें सिर्फ राजस्व (ऑपरेशनल) मद शामिल हैं।	इसमें राजस्व और पूँजी दोनों मद शामिल हैं।
परिभाषा	जब सरकार के नियमित कामकाज के खर्च (जैसे - वेतन, पेंशन और ब्याज का भुगतान) उसकी नियमित आय (जैसे - टैक्स और फीस) से अधिक हो जाते हैं, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं।	यह सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर है। यह बताता है कि सरकार को अपने पूरे साल के खर्चों को पूरा करने के लिए कुल कितने उधार की आवश्यकता है।
फॉर्मूला (सूत्र)	राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ।	कुल व्यय - (कुल राजस्व + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान का कैश प्लस मॉडल:

- बाल एवं मातृ कुपोषण से निपटने के लिए प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर और बारों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के लाभ हस्तांतरण को एकीकृत कर लागू किए 'राजस्थान कैश प्लस मॉडल' को केन्द्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में विशेष रूप से बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया है।

कम्प्रेहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम:

- केन्द्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्थान के कम्प्रेहेंसिव करियर एजुकेशन प्रोग्राम को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन और कौशल-आधारित सीख मिल रही है, जो रोजगार-उन्मुख शिक्षा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- साथ ही, सर्वे में ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राजस्थान में संस्थागत रूप में गाँवों के साझा प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग, दस्तावेजीकरण और संरक्षण को भी उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- इसी प्रकार, सर्वे में भवन योजना अनुमोदन के लिए राजस्थान में लागू किए गए थर्ड-पार्टी निरीक्षण जैसे सुधारों को भी बेस्ट प्रैक्टिसेज में शामिल किया गया है।

47वाँ मरु महोत्सव 2026 - जैसलमेर

चर्चा में क्यों?

- 30 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 47वें मरु महोत्सव (Jaisalmer Desert Festival) का आयोजन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- आयोजक : राजस्थान पर्यटन विभाग और ज़िला प्रशासन जैसलमेर।
- थीम : बीट्स ऑफ़ दी थार (Beats of the Thar)
- शुभारंभ : नेपालेश्वर महादेव मंदिर, पोकरण।

प्रमुख विजेता:

- मिस्टर डेजर्ट (मरु श्री) 2026 : मनीष पंवार (जैसलमेर)
- मिस मूमल 2026 : कुसुम पंवार (बीकानेर)
- मिस्टर पोकरण 2026 : मनीष सैन।
- मिस पोकरण 2026 : वर्षा भाटी।

--:4:--

नेशनल मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन - जयपुर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में नेशनल मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- **उद्घाटन** : राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी।
- **आयोजन** : 29 - 30 जनवरी, 2026 को RIC जयपुर में।
- **संस्करण** : 54वाँ।
- **विषय** : 'राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों के विकास एवं संरक्षण में मीडिया की भूमिका'।
- **उद्देश्य** : मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक भूमिका (चौथे स्तंभ) को मजबूत करना, पत्रकारों को जागरूक करना और उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडियाकर्मियों व समाज सेवियों को सम्मानित करना।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (RJHS)

- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा 04 अप्रैल, 2025 को 'राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (RJHS)' की अधिसूचना जारी की गई।
- ज्ञातव्य है कि पत्रकारों के लिए इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा भीलवाड़ा में 28 मार्च, 2025 को राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान किया गया था।
- योजना के तहत, राज्य सरकार से अधिस्वीकृत समस्त पत्रकार RJHS के लिए पात्र होंगे। इस योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद अधिस्वीकृत पत्रकारों को RGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

- योजना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा पात्र पत्रकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष की चिकित्सा व्यय (IPD) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- योजना में बीमित व्यक्ति को RGHS में परिभाषित अनुमोदित अस्पतालों में किए गए सभी इनडोर उपचारों तथा शल्य चिकित्साओं के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी।
- अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तथा पंद्रह दिन बाद तक की अवधि के दौरान किए गए प्रासंगिक चिकित्सा व्यय को दावे के हिस्से के रूप में माना जाएगा।
- RJHS योजना के तहत मातृत्व चिकित्सा, अन्तः रोगी उपचार (IPD) और अन्य चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना:

- 18 अप्रैल, 2025 को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा 'अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना' की अधिसूचना जारी की गई।
- यह योजना राज्य बजट 2024-25 की घोषणा के अनुरूप है, जो राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई है।

SERVICES

राजस्थान में अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT)

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित बालोतरा ज़िले में नगर विकास न्यास की स्थापना के साथ ही राज्य में कुल UITs की संख्या 12 हो गई है।



मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में बालोतरा में नए UIT के गठन की घोषणा कि गई थी।
- राजस्थान में अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT) जिसे नगर विकास न्यास के नाम से भी जाना जाता है एक वैधानिक निकाय है, जो शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास, विस्तार और बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- स्थापना** : राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (Rajasthan Urban Improvement Act, 1959) के तहत।

मुख्य कार्य :

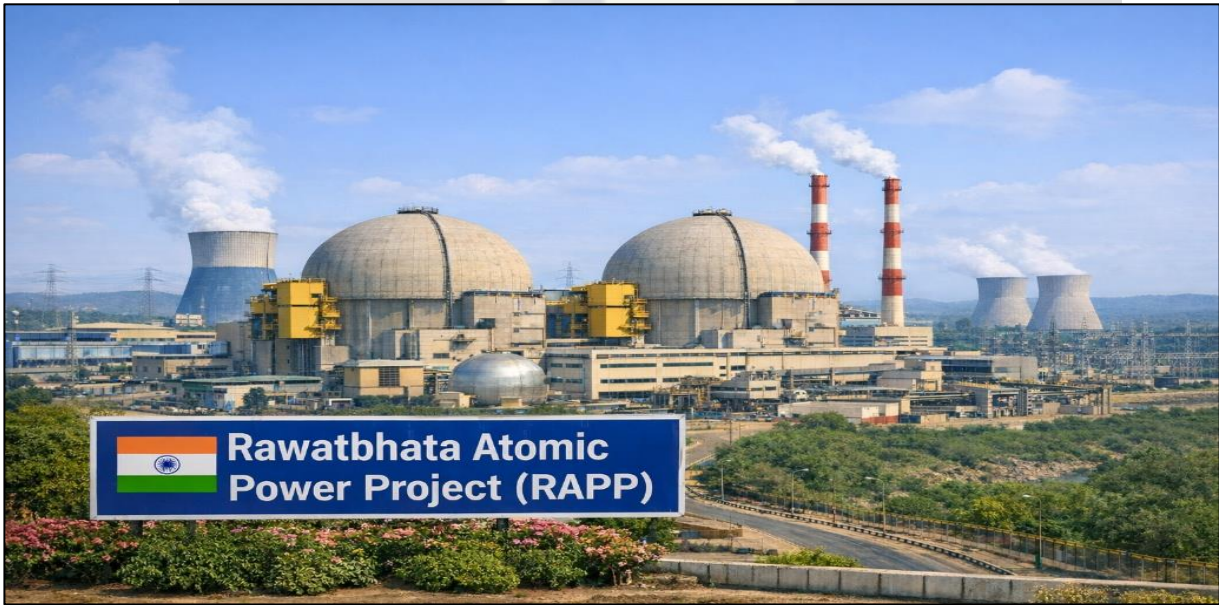
- नियोजित टाउनशिप और औद्योगिक गलियारों को प्रोत्साहन देना।
- शहरी शासन को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देना।
- आर्थिक विकास में तेज़ी लाना तथा अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना।
- वर्तमान में सक्रिय नगर विकास न्यास (UITs)** : माउंट आबू (सिरोही), अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, श्री गंगानगर, बालोतरा और दौसा-बांड़ीकुई।

--7--

रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) : चित्तौड़गढ़

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा देश की चौथी स्वदेशी तकनीक से निर्मित रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) की रिएक्टर इकाई 9 और 10 को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई।



मुख्य बिन्दु:

- वर्तमान में RAPP में कुल 7 परमाणु इकाइयाँ संचालित हैं जबकि आठवीं इकाई निर्माणाधीन है जिसके अप्रैल, 2026 में शुरू होने की संभावना है।

रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP)

- चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) राज्य का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें 7 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) इकाइयाँ संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1780 मेगावाट (MW) है।
- शुरुआत :** दिसम्बर, 1973 (सहयोग - कनाडा)
- संचालन :** न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)

--8:--

इकाई	उत्पादन
प्रथम इकाई	100 MW (वर्तमान में बंद)
द्वितीय इकाई	200 MW
तृतीय इकाई	220 MW
चतुर्थ इकाई	220 MW
पंचम इकाई	220 MW
षष्ठम इकाई	220 MW
सप्तम इकाई	700 MW
अष्टम इकाई	निर्माणाधीन
कुल उत्पादन	1780 मेगावाट (MW)

- **PHWR** : प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR) एक प्रकार का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होता है, जो भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड/D2O) को शीतलक और न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में उपयोग करता है और प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में करता है।
- **भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, रख-रखाव और निगरानी हेतु नोडल एजेंसी** : न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स**:
- **राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र** : माही बाँसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट (MBRAPP)
- **रिएक्टर** : इस परियोजना के अंतर्गत 700 मेगावाट क्षमता के 4 परमाणु रिएक्टर (700x4) स्थापित किए जाएँगे।
- वर्ष 2033 से इस संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना है।
- **प्रकार** : प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR)
- **कंपनी** : अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी)
- यह देश में स्थापित होने वाला 9वाँ परमाणु रिएक्टर होगा।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>रणथम्भौर नेशनल पार्क में मोबाईल फोन के उपयोग पर रोक</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, राजस्थान वन विभाग द्वारा रणथम्भौर नेशनल पार्क (सवाई माधोपुर) में पर्यटकों के मोबाईल उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की। रणथम्भौर नेशनल पार्क इस प्रकार के नियम लागू करने वाला राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है।यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन की पालना में लिया गया है।
2.	<p>7वीं ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन : पटेल स्टेडियम, अजमेर।अवधि : 29 जनवरी से 2 फरवरी 2026।
3.	<p>क्रिकेट अंपायर रघुवीर सिंह राठौड़ का निधन</p> <ul style="list-style-type: none">पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर और शिक्षाविद् प्रोफेसर रघुवीर सिंह राठौड़ का 30 जनवरी, 2026 को निधन हो गया।प्रोफेसर राठौड़ उदयपुर के रहने वाले थे तथा उन्होंने 2 टेस्ट मैच और 4 वनडे मैचों में अंपायरिंग की थी। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी मैचों में भी अंपायरिंग की।
4.	<p>'ऑपरेशन नॉकआउट'</p> <ul style="list-style-type: none">'ऑपरेशन नॉकआउट' (Operation Knockout) राजस्थान पुलिस (जयपुर ग्रामीण) द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों (ड्रग्स) के अवैध व्यापार और तस्करी पर प्रतिबंध लगाना है।
5.	<p>चतुर्थ कुलगुरु चल वैजयन्ती खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता</p> <ul style="list-style-type: none">आयोजन : 30 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक।स्थान : राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (RARI), दुर्गापुरा, जयपुर।उद्देश्य : इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों में टीम भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है।

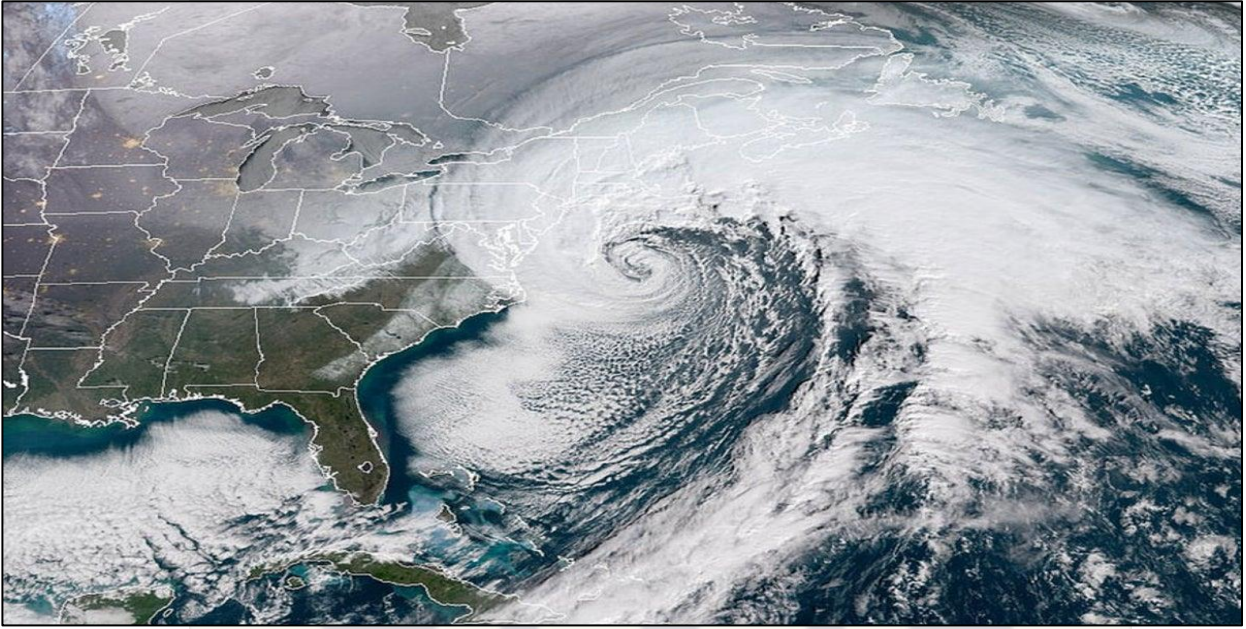
6.	<p style="text-align: center;">मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।■ इसके तहत राज्य के सभी जिलों में 25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार तथा अनुसूचित जनजाति (ST) बाहुल्य 8 जिलों के 47 ब्लॉकों में 50 अतिरिक्त दिवस का रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान है।■ नोट : हाल ही में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य के लंबित सामग्री मद भुगतान के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹827.86 करोड़ रुपये की नई किश्त जारी की।
7.	<p style="text-align: center;">छांपाला भैरू जी महाराज का लक्खी मेला</p> <ul style="list-style-type: none">■ कोटपूतली-बहरोड़ के कुहाड़ा गाँव में हाल ही में छांपाला भैरू जी महाराज का लक्खी मेला सम्पन्न हुआ।■ इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 'महाप्रसादी' है। इसमें 651 क्विंटल चूरमा तैयार किया जाता है, जिसे बनाने के लिए JCB, थ्रेसर और कंप्रेसर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है।
8.	<p style="text-align: center;">राजस्थान की झाँकी को पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड</p> <ul style="list-style-type: none">■ 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल राजस्थान की झाँकी को पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।■ पुरस्कार प्रदानकर्ता : रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ द्वारा राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन, कला, साहित्य एवं संस्कृति) प्रवीण गुप्ता को दिया गया।■ ज्ञातव्य है कि नागरिकों को अपनी पसंदीदा झाँकी और मार्चिंग दस्ते के लिए मतदान करने हेतु माईगव पोर्टल (MyGov) पर किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण में राजस्थान की झाँकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।■ प्रथम और द्वितीय स्थान क्रमशः गुजरात और उत्तर प्रदेश की झाँकियों का रहा।■ राजस्थान की झाँकी का विषय : रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श : बीकानेर की स्वर्ण कला (उस्ता कला)।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

बम चक्रवात (Bomb Cyclone)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, उत्तरी अमेरिका में एक बम चक्रवात आया। इससे तीव्र ठण्ड, तेज हवाएँ और भारी बर्फबारी जैसी गंभीर मौसम संबंधी स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं।



मुख्य बिन्दु:

- **उत्पत्ति:** जब तीव्र निम्नदाब वाली वायुराशि उच्चदाब वाली वायुराशि से टकराती है, इस प्रक्रिया को बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है।
- **विशेषताएँ:** 24 घंटे के भीतर वायुमण्डलीय वायुदाब में कम से कम 24 मिलिबार की गिरावट दर्ज की जाती है।
- वायुमण्डलीय दाब ये अचानक गिरावट के कारण दाब प्रवणता बल में वृद्धि से हवाएँ प्रबल होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है।
- **उत्पत्ति क्षेत्र:** ये सर्वाधिक पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं। इसका कारण है, उत्तरी अमेरिका की शीत वायुराशि तथा अटलांटिक महासागर के ऊपर की गर्म वायु राशि का अभिसरण।

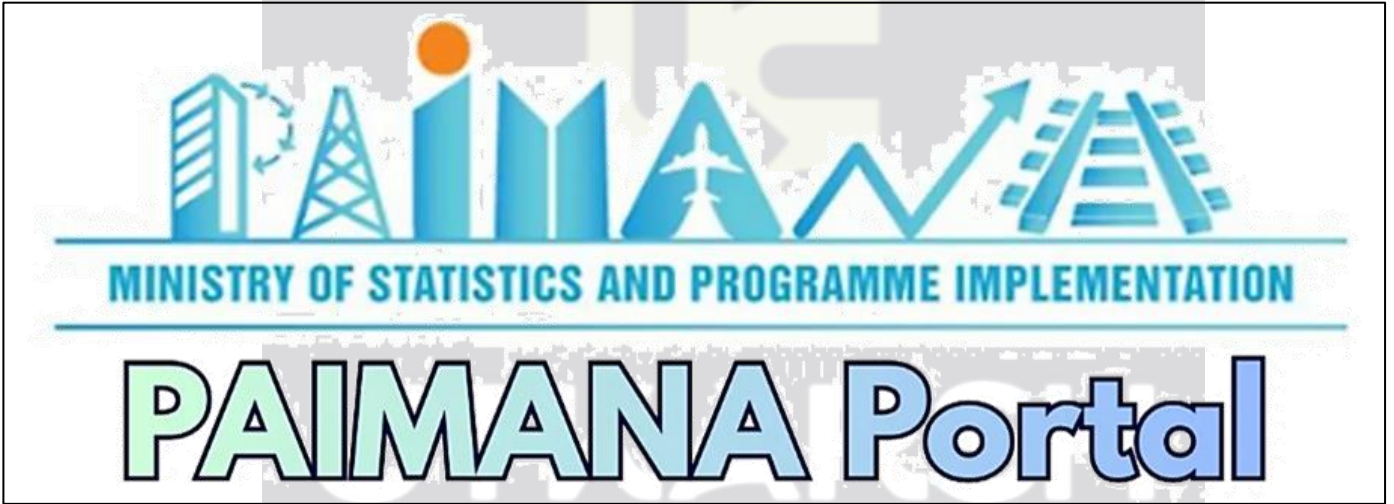
--:12:--

आर्थिक घटनाक्रम

PAIMANA

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, PAIMANA नामक एक नया वेब आधारित पोर्टल क्रियान्वित किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

- पूर्ण रूप:** राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना निगरानी और विश्लेषण। (Project Assessment, Infrastructure Monitoring Analytics for Nation Building)
- संचालन:** यह एक वेब आधारित पोर्टल है। इसे केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित।
- निगरानी:** इसने OCMS-2006 (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली) की जगह ली है। इसका उपयोग 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए किया जाएगा।
- यह पोर्टल “वन डेटा, वन एंट्री” सिद्धांत पर कार्य करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 की मुख्य बातें

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया।

मुख्य बिन्दु:

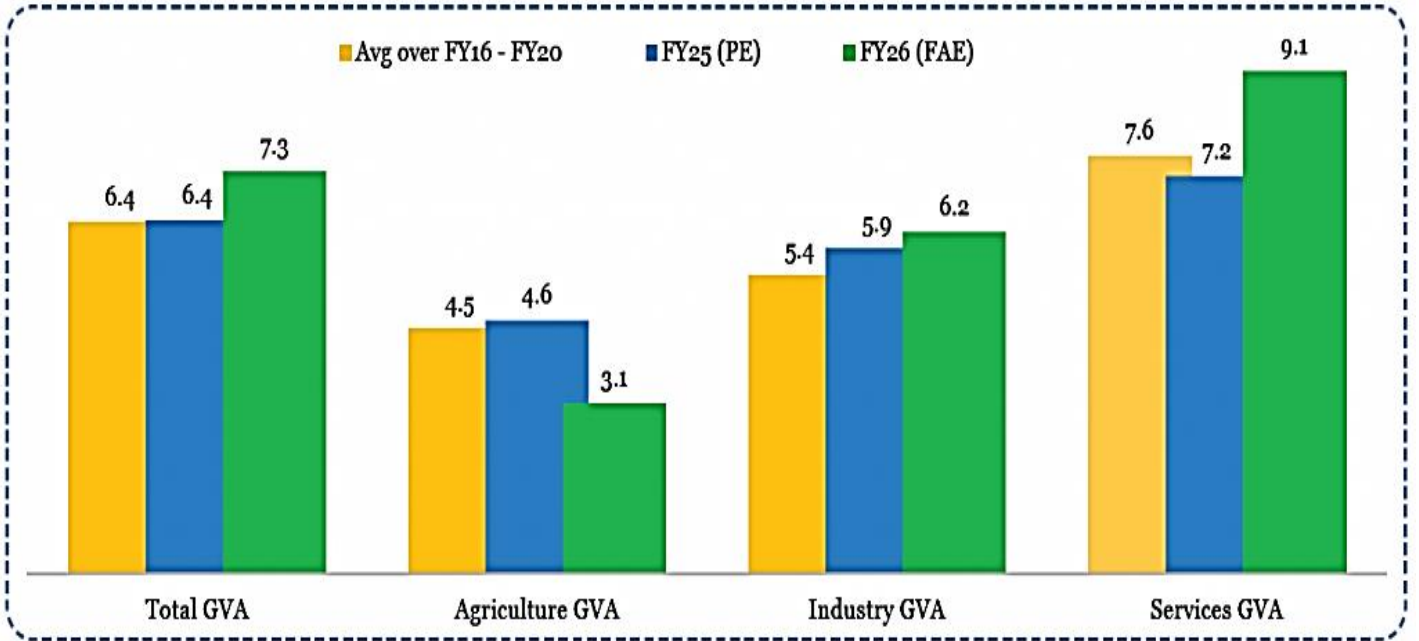
आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

- यह एक आधिकारिक वार्षिक दस्तावेज है जो पिछले वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है और प्रमुख आर्थिक रुझानों, चुनौतियों और नीतिगत दिशाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की मुख्य बातें

- वैश्विक संदर्भ और भारत का विकास लाभ:** भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन और वित्तीय कमजोरियों से ग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक बनी हुई है।
- भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
- पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू बुनियादी बातों को रेखांकित करता है।

Broad-Based Growth in Real Gross Value Added (%)



माँग आधारित विकास: उपभोग और निवेश

- **उपभोग की गति:** वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.0% की वृद्धि हुई, जो जीडीपी का 61.5% तक पहुँच गया, जो 2012 के बाद से उच्चतम स्तर है।
- यह कम और स्थिर मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार स्थितियों और बढ़ती वास्तविक आय को दर्शाता है।
- मजबूत कृषि उत्पादन ने ग्रामीण खपत को बढ़ावा दिया, जबकि कर युक्तिकरण और आय वृद्धि ने शहरी माँग को समर्थन दिया, जो व्यापक स्तर पर खपत में सुधार का संकेत देता है।
- **निवेश में पुनरुत्थान:** सकल स्थिर पूँजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 30% बनी रही। निवेश वृद्धि को निरंतर सार्वजनिक पूँजीगत व्यय और निजी क्षेत्र के नए निवेश से समर्थन मिला, जो कंपनियों की घोषणाओं में परिलक्षित हुआ।

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

- **विकास के इंजन के रूप में सेवाएँ:** सेवाएँ विकास का प्राथमिक चालक बनी हुई हैं:
- वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सकल लाभ में 9.3% की वृद्धि।
- पूरे वर्ष के लिए अनुमानित 9.1% की वृद्धि: आधुनिक, व्यापार योग्य और डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण, सेवाओं का अब कुल सकल मूल्य (GVA) में 56.4% हिस्सा है।
- **उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में उछाल:** वैश्विक चुनौतियों के बावजूद औद्योगिक गतिविधियों में मजबूती आई।
- वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में उद्योग के सकल बाजार मूल्य में 7.0% की वृद्धि हुई।
- विनिर्माण सकल बाजार मूल्य में पहली तिमाही में 7.72% और दूसरी तिमाही में 9.13% की वृद्धि दर्ज की गई।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है।

वित्तीय घटनाक्रम

प्रमुख वित्तीय रुझानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति 9.2% तक बढ़ गई।
- गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.4% (महामारी से पहले) से बढ़कर 3.3% हो गया है।
- आयकर दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है।

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि हुई:

- वित्त वर्ष 2025 में प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4% तक पहुँच गया।
- राज्यों को पूंजीगत व्यय को बनाए रखने के लिए लक्षित सहायता के माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया।
- भारत ने 2020 से अपने सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 7.1 प्रतिशत अंक तक कम कर दिया है, जबकि निवेश का स्तर उच्च बना हुआ है।

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

- **बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें सकल राष्ट्रीय परिसंपत्ति बकाया (GNPA) 2.2% और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बकाया (NET NPA) 0.5% (सितंबर, 2025) है।

बाह्य क्षेत्र: अस्थिर दुनिया में लचीलापन

- वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 1.8% हो गई, और सेवा निर्यात में 4.3% हो गई।
- सेवाओं के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.3% पर बना रहा (वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही)।
- प्रेषण की राशि 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है।
- विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो लगभग 11 महीनों के आयात को कवर करता है।
- भारत ने ग्रीनफील्ड निवेश में वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया और डिजिटल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा (2020-24)।

मुद्रास्फीति

- भारत में अब तक की सबसे कम सीपीआई मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जिसमें औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 1.7% (अप्रैल-दिसंबर 2025) रही।
- इसका कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में गिरावट और प्रभावी आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन था।
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, भारत में 2025 के दौरान मुद्रास्फीति में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 357.7 मिलियन टन तक पहुँच गया।
- बागवानी का उत्पादन 362.08 मीट्रिक टन रहा, जो खाद्यान्न उत्पादन से अधिक था और कृषि सकल मूल्य का 33% था।
- डिजिटल और बाजार सुधारों ने E-NAM की पहुँच का विस्तार किया, जिससे 1.79 करोड़ किसानों को लाभ हुआ।
- MSP, पीएम-किसान और पीएमकेएमवाई पेंशन के माध्यम से आय सहायता जारी रही।

उद्योग और विनिर्माण

- वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में उद्योग का सकल बाजार मूल्य 7.0% बढ़ा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर दूसरी तिमाही में बढ़कर 9.13% हो गई।
- पीएलआई योजनाओं ने 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया और 12.6 लाख नौकरियाँ सृजित कीं।
- भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में सुधार हुआ है और वह 2025 में 38वें स्थान पर पहुँच गई है।
- सेमीकंडक्टर मिशन ने 1.6 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी।

मानव पूँजी: शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल

- **शिक्षा:** 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ छात्र नामांकित, उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़कर 70,018 हो गई, एनईपी सुधारों ने लचीली शिक्षा, क्रेडिट पोर्टेबिलिटी और कौशल एकीकरण को सक्षम बनाया।
- **स्वास्थ्य:** 1990 से मातृ मृत्यु दर में 86% की गिरावट आई है, शिशु मृत्यु दर घटकर 25 (2023) हो गई है, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की गिरावट आई है।
- **रोजगार, कौशल और सामाजिक प्रगति:** वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 56.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला,
- ई-श्रम कार्यक्रम में 31 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जिनमें 54% से अधिक महिलाएँ हैं।

ग्रामीण विकास और सामाजिक प्रगति

- संशोधित वैश्विक मानकों के तहत गरीबी के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई। सामाजिक सेवाओं पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 7.9% तक बढ़ गया, जबकि ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व, डिजिटल मानचित्रण और महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों ने जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी को मजबूत किया।

उभरते क्षेत्र: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शहरीकरण और रणनीतिक लचीलापन

- भारत का एआई इकोसिस्टम व्यावहारिक, कम लागत वाले और स्थानीय समाधानों के इर्द-गिर्द विकसित हो रहा है, जिससे कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शासन जैसे क्षेत्रों में इसे अपनाने में मदद मिल रही है।
- शहरी संपर्क परियोजनाएँ श्रम बाजारों को नया आकार दे रही हैं और महानगरों के दबाव को कम कर रही हैं।
- रणनीतिक रूप से, भारत संकीर्ण आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन और वैश्विक अपरिहार्यता की ओर अग्रसर हो रहा है, और खुद को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से समाहित कर रहा है।

रणनीतिक लचीलापन और अपरिहार्यता

- भारत की विकास रणनीति आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन और वैश्विक अपरिहार्यता की ओर विकसित हो रही है।
- एक अनुशासित स्वदेशीकरण ढाँचा, कम इनपुट लागत, वास्तविक दुनिया की जरूरतों के अनुरूप एआई का प्रसार और एकीकृत शहरीकरण मॉडल भारत को 'भारतीय उत्पाद खरीदने' से 'बिना सोचे-समझे भारतीय उत्पाद खरीदने' की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26: भारत एक 'उद्यमशील राज्य'



चर्चा में क्यों?

- आर्थिक सर्वेक्षण, 2025-26 भारत के एक 'उद्यमशील राज्य' (Entrepreneurial State) की ओर संक्रमण का आह्वान करता है।



मुख्य बिन्दु:

"उद्यमशील राज्य" का क्या अर्थ है?

- यह अवधारणा अर्थशास्त्री मारियाना माज़ुकाटो ने लोकप्रिय बनाई थी।

विशेषताएँ:

- **जोखिम का संरचनाकरण:** उद्यमशील राज्य वह है जो अनिश्चितता से डरकर पीछे नहीं हटता। सरकार जोखिम से बचने की बजाय उसे सक्रिय रूप से समझकर और व्यवस्थित रूप से निपटने का प्रयास करती है।
- **संस्थागत रूप से सीखना:** इसमें "अनुपालन से क्षमता" की ओर बढ़ना शामिल है, जहाँ राज्य "असफल होना सीखता है यानी असफलताओं को स्वीकार करता है"। साथ ही, नीतिगत पंगुता के बिना तेजी से सुधार करता है।
- **उदाहरण:** दक्षिण कोरिया ने राज्य क्षमता का निर्माण सिर्फ प्रशासनिक साहस से नहीं किया। उसने संस्थानों को सोची-समझी और चरणबद्ध तरीके से विकसित किया।

नौकरशाही की विशेषताएँ:

- **परिणाम-उन्मुख नौकरशाही:** अधिकारियों का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर किया जाता है, न कि केवल नियमों के पालन पर।
- **सीखने के साथ विफलता के प्रति सहनशीलता:** त्रुटियाँ स्वीकार्य होती हैं, लेकिन ठहराव स्वीकार्य नहीं है।

Daily Current Affairs

Date : 31 January, 2026



- **समर्थन की विश्वसनीय वापसी:** बाहर निकलना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि प्रवेश करना। इसका अर्थ है किसी संस्था आदि को समय के अनुसार समर्थन देना बंद कर देना चाहिए।

यह क्या 'नहीं' है?

- इसका अर्थ राज्य का व्यावसायीकरण (जैसे- राज्य पूंजीवाद) नहीं है, और न ही यह निजी हितों को विशेषाधिकार देने का सुझाव देता है।
- इसका उद्देश्य राज्य को निजी क्षेत्र के नवाचार में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाना है।
- आर्थिक सर्वेक्षण सुझाव देता है कि एक उद्यमशील राज्य के लिए श्रम के सूक्ष्म विभाजन की आवश्यकता है—राजनीतिक नेतृत्व दिशा निर्धारित करता है और प्राथमिकताएँ स्पष्ट करता है, जबकि नौकरशाही मार्ग खोजती है, समस्याओं का समाधान करती है और नीतिगत साधनों को अनुकूलित करती है।

--:21:--

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

विश्व परमाणु परिदृश्य रिपोर्ट



मुख्य बिन्दु:

- विश्व परमाणु संघ ने विश्व परमाणु परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है।
- यह रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा के भविष्य के लिए एक अत्यन्त सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती है।

